[2015] 1 एस. सी. आर. 437

जेटी. कलेक्टर रंगा रेड्डी जिला और अन्य आदि .....अपीलार्थीगण

बनाम

डी. नरसिंग राव और अन्य आदि .....प्रतिवादीगण

(सिविल अपील संख्या 325-326/2015)

13 जनवरी, 2015

[न्यायाधिपति सी. नागप्पन और न्यायाधिपति टी. एस. ठाकुर]

आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि राजस्व अधिनियम,1317 एफ – धारा 166 बी लंबे समय (लगभग 50 वर्ष) के बाद स्वत: संज्ञान से संशोधन किया गया - अनुमेयता - धारा 1668 के तहत नोटिस - भूमि के मालिक होने का दावा करने वाले उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती दी गई क्योंकि उनके हित पूर्ववर्तियों के नाम खसरा पिहानी में उल्लिखित थे। वर्ष 1954-55 - निचली अदालतों ने नोटिस को रद्द कर दिया - अपील पर, आयोजित: यद्यपि स्वत: संज्ञान संशोधन करने के लिए कोई सीमा प्रदान नहीं की गई है, 50 वर्षों के बाद इसका अभ्यास मनमाना और अनुचित है और कानून की अवधारणा के विपरीत है- आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि विनियमन में अधिकारों का रिकॉर्ड, 135 बीएफ - विनियमन 13 - आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) (जागीरों का उन्मूलन) विनियमन, 1358 एफ - सीमा।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

आयोजित:

न्यायाधिपति सी. नागप्पन 1. 1948 में हैदराबाद राज्य के भारत में विलय के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) जागीर उन्मूलन विनियमन, 1358 फसली द्वारा जागीरें समाप्त कर दी गईं। 'खसरा पहानी' वर्ष 1954-55 में राजस्व बोर्ड आंध्र प्रदेश द्वारा तैयार किया गया अधिकारों का मूल रिकॉर्ड है। इसे एपी (तेलंगाना क्षेत्र)भूमि विनियमन 1358 एफ में अधिकारों के रिकॉर्ड के विनियमन 4 के तहत राजपत्रित किया गया था। विनियम संख्या 13 के अनुसार अधिकारों के उक्त रिकॉर्ड में कोई प्रविष्टि जब तक विपरीत साबित न हो जाए, तब तक इसे सत्य माना जाएगा। 1358-एफ का उक्त विनियमन तब तक प्रचलन में था, जब तक इसे एपी भूमि और पट्टादार पासबुक अधिनियम, 1971 में अधिकार द्वारा निरस्त नहीं कर दिया गया, जो 15.8.1978 को लागू हुआ। उत्तरदाताओं के स्वामित्व में पूर्ववर्तियों के नाम प्रश्नगत भूमि से संबंधित वर्ष 1954-55 के खसरा पहानी में उल्लिखित पाए जाते हैं। पंजीकृत बिक्री कार्यों के तहत प्रतिवादियों द्वारा उनसे उक्त भूमि की खरीद भी गंभीर रूप से विवादित नहीं है। वे वर्ष 1954 से लगातार नियमित रूप से भू-राजस्व का भुगतान भी कर रहे हैं। राज्य ने ए.पी. की धारा 1668 के तहत दिनांक 31.12.2004 को विवादित नोटिस जारी किया (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि राजस्व अधिनियम, 1317 एफ (1907) वर्ष 1953-54 के खसरा पहानी में प्रविष्टियों को रद्द करने के लिए।

[पैरा 9-1 ओ] [450-जी-एच; 451-ए-बी, सी-ई]

2. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि विनियमन में अधिकारों का रिकॉर्ड, 1358F में स्वत: संज्ञान शक्ति के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। दिनांक 24.9.1991 के सरकारी आदेश (सरकारी कर्मचारियों के लिए घर-स्थलों के लिए भूमि आरक्षित करना) को पारित करते समय सरकार के पास भूमि से संबंधित राजस्व प्रविष्टियों को सत्यापित करने का हर अवसर था, लेकिन पाई गई प्रविष्टियों पर कोई अपवाद नहीं लिया गया। यहां तक कि जब सरकारी आदेश दिनांक 24.9.1991 को चुनौती दी गई, तब भी उक्त प्रविष्टियों के संबंध में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई सर्वेक्षण संख्या. प्रतिवादी नंबर 1 और 2 से भूमि के खरीददारों द्वारा मुकदमा, एक घोषणा के लिए प्रार्थना करते हुए कि वे वैध मालिक थे और सर्वेक्षण संख्या 36 में भूमि के कुछ भूखंडों के मालिक थे, को डिक्री कर दिया गया था और कहा गया था कि डिक्री को अंतिम बनने की अनुमति दी गई थी। दिनांक 31.12.2004 के आक्षेपित नोटिस द्वारा विनियम 1668 के तहत स्वत: संशोधन शक्ति का प्रयोग पांच दशकों के बाद करने की मांग की गई थी। लंबे समय के अंतराल के बाद, यहां तक कि किसी भी समय सीमा के अभाव में भी स्वत: संज्ञान से किया गया संशोधन मनमाना था और कानून के शासन की अवधारणा के विपरीत था। [पैरा 11-12] [452-ई-एच; 453-ए-बी, सी-डी]

कलेक्टर और अन्य बनाम पी. मंगम्मा और अन्य 2003(2) एससीआर 430 = 2003 (4) एसईसी 488 (2003) 4 एसईसी 488; महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम रतनलाल 1992 (3) सप्ल एससीआर 536 =(1993) 3 एससीसी 326; उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम ब्रुंदबन शर्मा और अन्य (1995) अनुपूरक (3) एससीसी 249; गुजरात राज्य बनाम पाटिल राघव नाथा और अन्य (1969) 2 एससीसी 187; मोहम्मद कवि मोहम्मद अमीन बनाम फातमाबाई इब्राहिम (1997) 6 एससीसी 71; संतोषकुमार शिवगोंडा पाटिल और अन्य बनाम बालासाहेब तुकाराम शेवाले और अन्य (2009) 9 एससीसी 352; पंजाब राज्य और अन्य बनाम भटिंडा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड 2007(11) एससीआर 14 = (2007) 11 एससीसी 363; ब्राहिमपटनम तालुक व्यवसायी कुली संघम बनाम के सुरेश रेड्डी और अन्य 2003 (2) पूरक एससीआर 698 = (2003) 7 एससीसी 667 - संदर्भित।

प्रति न्यायाधिपति टी.एस. ठाकुर (पूरक):

1. यदि कार्य या लेन-देन हमेशा चुनौती के लिए खुले रहेंगे, तो इसका मतलब मानवीय मामलों में टालने योग्य और अंतहीन अनिश्चितता होगी, जो कानून की नीति नहीं है। क्योंकि, जब ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं होती है, तब भी हस्तक्षेप की देरी, तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण का कारण बन सकती है, जिसे विवेकाधीन शक्ति के विलंबित अभ्यास द्वारा कुचला नहीं जा सकता है, खासकर जब देरी के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है दृष्टि में है कि कानून का नियम

जीवन के नियम के साथ निकटता से चलना चाहिए। यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां संशोधित किए जाने वाले आदेश धोखाधड़ी वाले हैं, शक्ति का प्रयोग धोखाधड़ी की खोज की उचित अवधि के भीतर होना चाहिए। किसी कार्य या लेन-देन को कपटपूर्ण बताने मात्र से उसके सुधार के लिए लगने वाला समय अनंत तक नहीं बढ़ जाएगा; अन्यथा पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग स्वयं उस क़ानून के साथ धोखाधड़ी के समान होगा जो ऐसी शक्ति किसी प्राधिकारी को प्रदान करता है।

[पैरा 11] [460-बी-डी]

2. वर्तमान मामले में, जबकि सुधार की मांग की गई प्रविष्टि को धोखाधड़ी के रूप में वर्णित किया गया है, उच्च न्यायालय के समक्ष लगाए गए नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि राज्य द्वारा कथित धोखाधड़ी की खोज कब की गई थी। उस संबंध में एक विशिष्ट बयान आवश्यक था, क्योंकि यह एक न्यायिक तथ्य था, जिसे उत्तरदाताओं को जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। अपीलकर्ता-राज्य का यह प्रदर्शित करने का प्रयास कि कथित धोखाधड़ी की खोज की उचित अवधि के भीतर नोटिस जारी किया गया था, इसलिए व्यर्थ है। [पैरा 12] [460-ई-जी]

3. जब सरकार ने वर्ष 1991 में आवास स्थलों के लिए संबंधित भूमि को सरकारी कर्मचारियों को देने की अनुमति दी, तो यह माना जाना चाहिए कि उसे आधिकारिक व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए भूमि के पार्सल से

संबंधित रिकॉर्ड और राजस्व प्रविष्टियों के बारे में पता था। कुल मिलाकर, नोटिस 31 दिसंबर 2004 को देर से जारी किया गया था, इसमें लगभग 13 साल की देरी हुई थी। इस देरी के लिए भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, यह मानते हुए कि इसे केवल वर्ष 1991 से गिना जाना चाहिए। आधी सदी पहले की गई प्रविष्टियों को उलटने की मांग करने वाला नोटिस स्पष्ट रूप से उचित समय से परे था और इसे सही ढंग से रद्द कर दिया गया था। [पैरा 12] [460-जी-एच; 461-ए]

संतोषकुमार शिवगोंडा पाटिल और अन्य बनाम बालासाहेब तुकाराम शेवाले (2009) 9 एससीसी 352 और विशेष निदेशक और अन्य बनाम मोहम्मद गुलाम घोष और अन्य 2004(1) एससीआर 399 = (2004) 3 एससीसी 440; एस.बी. गुरबख्श सिंह व्युनियन ऑफ इंडिया 1976 (3) एससीआर 247 = 1976 (2) एससीसी 181, इब्राहिमपटनम तालुक व्यवसायी कुली संघम बनाम के. सुरेश रेड्डी और अन्य 2003 (2) पूरक एससीआर 698 =(2003)7 एससीसी 667; सुलोचना चंद्रकांत गलांडे बनाम पुणे नगरपालिका परिवहन और अन्य (2010) 8 एससीसी 467; हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम राजकुमार बृजेन्द्र सिंह एवं अन्य 2004(1) पूरक एससीआर 618 =2004 (10) एससीसी 585; मिस डेहरी रोहतास लाइट रेलवे कंपनी लिमिटेड बनाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, भोजपुर और अन्य 1992 (2) एससीआर 155 = (1992) 2 एसईसी 598 - पर भरोसा किया।

वाद कानून संदर्भ

न्यायाधिपति नागप्पन के फैसले में

2003 (2) एससीआर 430 संदर्भित पैरा 7

1992 (3) सप्ल एससीआर 536 संदर्भित पैरा 7

(1995) अनुपूरक(3)एसईसी249 संदर्भित पैरा 7

(1969) 2 एसईसी 187 संदर्भित पैरा 8

(1997) 6 एसईसी 71 संदर्भित पैरा 8

(2009) 9 एसईसी 352 संदर्भित पैरा 8

2007 (11) एससीआर 14 संदर्भित पैरा 8

2003 (2) पूरक एससीआर 698 संदर्भित पैरा 8

न्यायाधिपति ठाकुर के फैसले में

(2009) 9 एसईसी 352 भरोसा किया पैरा 4

2004 (1) एससीआर 399 निर्भर पैरा 4

1976 (3) एससीआर 247 निर्भर पैरा 6

2003 (2) पूरक एससीआर 698 निर्भर पैरा 7

2004 (1) पूरक। एससीआर 618 निर्भर पैरा 8

2004 (1 0) एसईसी 585 निर्भर पैरा 9

1992 (2) एससीआर 155 निर्भर पैरा 10

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 325-326/2015

2010 के डब्ल्यूपी संख्या 273 और 323 में हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 08.06.2010 से।

साथ

2015 की सिविल अपील संख्या 327।

एल.एन. राव, एएसजी, आर. वेंकटरामनी, डी. महेश बाबू, सुचित्रा ह्लांगखॉल, अमित के. नैन, जी.एन. अपीलकर्ताओं के लिए रेड्डी, योगेश जोगिया हेमेंद्र रेड्डी, अमित सूद, हेतु अरोरा सेठी।

यू यू ललित, प्रवीण एच. पारेख, रंजीत कुमार, पी.वी. शेट्टी, एस आदि नारायण, ललित चौहान, सुमित गोयल, सोमनदारी गौड़, शशांक भंसाली, रितिका सेठी, अभिषेक विनोद देशमुख (पारेख एंड कंपनी के लिए), वेंकटेश्वर राव अनुमोलू, प्रभाकर परनाम, वाई. राजगोपाल राव, हितेंद्र नाथ रथ, विस्मा भारती उत्तरदाताओं के लिए रेड्डी, डी. रामकृष्ण रेड्डी, सतीश गल्ला, एन. राजारमन, ए.एस. राव, राम स्वरूप शर्मा, वाई. राजा गोपालराव, जी.एन. रेड्डी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

न्यायाधिपति सी. नागप्पन 1. अनुमति स्वीकृत।

2. ये अपीलें हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2010 की रिट अपील संख्या 273 और 323 में पारित सामान्य निर्णय दिनांक 8.6.2010 के खिलाफ निर्देशित हैं।

3. मोटे तौर पर, इन अपीलों को दायर करने के तथ्य इस प्रकार हैं: इसमें कोई विवाद नहीं है कि रंगा रेड्डी जिले में गोपनपल्ली गांव एक जागीर गांव था। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार सर्वेक्षण संख्या 36 और 37, जिनकी माप एसी 280.00 गुंटा और एसी 378.14 गुंटा है, उक्त गांव की जागीर भूमि थी और जागीरदार ने अलग-अलग व्यक्तियों को पट्टे दे दिए थे, जो जमीन पर काबिज थे और जागीर के उन्मूलन के बाद भी वही परिलक्षित हुआ। वर्ष 1954-55 के लिए खसरा पहानी में पट्टे के रूप में, जो आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि विनियमन में अधिकारों के रिकॉर्ड की धारा 4 (2) के तहत तैयार किया गया था, और बाद में पट्टादारों ने पंजीकृत बिक्री कार्यों के तहत याचिकाकर्ताओं को भूमि हस्तांतरित कर दी थी और उन्होंने उसी पर उनका कब्ज़ा है. यह उनका आगे का मामला है कि सर्वेक्षण संख्या 36 में एकड़ 44-00 की सीमा तक और सर्वेक्षण संख्या 37 में एकड़ 46-00 की सीमा तक पट्टा दिया गया था और जब मामला इस प्रकार था, तो जांच करने पर याचिकाकर्ताओं को पता चला। कि सरकार ने

सरकारी आदेश दिनांक 10.7.1991 और 24.9.1991 द्वारा गोपनपल्ली गांव के सर्वेक्षण संख्या 36 और 37 में कुल 477 एकड़ भूमि को सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास स्थलों के लिए आरक्षित और आवंटित किया है, सर्वेक्षण संख्या के उपखंड संख्या का उल्लेख किए बिना। और याचिकाकर्ताओं की पट्टा भूमि को भी आरक्षित क्षेत्र में शामिल करने की मांग की गई है और याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की फाइल पर 1997 की रिट याचिका संख्या 21719 दायर करके इसे चुनौती दी है।

रिट याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रतिवादी नंबर 2 के कहने पर रिट याचिकाकर्ताओं और अन्य को दिनांक 19.12.2003 को नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि वर्ष 1953-54 के लिए भूमि स्वामित्व के संबंध में रिकॉर्ड यानी फैसल पट्टी के सत्यापन पर गोपनपल्ली गाँव के सर्वेक्षण संख्या 36 और 37 में उक्त भूमि के संबंध में कोई "ऐन लज़फ़ा" (यानी) (परिवर्तनों का कार्यान्वयन) नहीं हुआ है और खसरा पिहानी में प्रविष्टियाँ तत्कालीन पटवारी द्वारा आदेश के बिना शामिल की गई प्रतीत होती हैं सक्षम प्राधिकारी और पट्टादार पासबुक अधिनियम, 1971 की भूमि में आंध्र प्रदेश अधिकार की धारा 9 के तहत एक जांच, 27.12.2003 को सुनवाई के लिए निर्धारित है और रिट याचिकाकर्ताओं ने 2003 की रिट याचिका संख्या 26987 दायर करके उक्त नोटिस को चुनौती दी और विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा। उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.8.2004 के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और

आक्षेपित कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे कहा गया है कि पहले प्रतिवादी ने उसी आधार पर आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि राजस्व अधिनियम, 1317F की धारा 1668 के तहत पूछताछ के लिए दिनांक 31.12.2004 को नोटिस जारी किया, जिसमें सुनवाई की तारीख 5.2.2005 तय की गई और याचिकाकर्ताओं ने 2005 की अपनी रिट याचिका संख्या 1731 में इसे चुनौती दी और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दोनों रिट याचिकाओं यानी 1997 की 21719 और 2005 की 1731 की एक साथ सुनवाई की।

4. उक्त रिट याचिकाओं का सरकार द्वारा यह कहकर विरोध किया गया कि आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) (जागीरों का उन्मूलन) विनियमन, 1358 फसली द्वारा 15.8.1948 को जागीरें समाप्त कर दी गई थीं और सभी जागीरों में पहले से मौजूद अधिकार थे छीन लिया गया और वर्ष 1954-55 के खसरा पहानी के अनुसार ग्राम गोपनपल्ली के सर्वेक्षण संख्या 36 और 37 के तहत उपविभागों को पटवारी द्वारा धोखाधड़ी से बनाया गया था और उन उपविभागों और नामों को फैसल पट्टी में निज़ाम जमाबंदी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। वर्ष 1954-55 प्रचलित प्रक्रिया और अनुसूची के अनुसार 15.8.1948 को जागीर उन्मूलन के समय से सर्वेक्षण संख्या 36 और 37 वाली भूमि को चिन्ना कांचा (चरागाह भूमि) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह सरकार और उक्त अनधिकृत प्रविष्टियों से संबंधित है। तत्कालीन

पटवारी द्वारा किए गए खसरा पहानी में राजस्व अधिकारियों द्वारा पता लगाया गया था और इसलिए आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि राजस्व अधिनियम, 1317 एफ की धारा 1668 के तहत जांच का आदेश दिया गया है और केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने सामान्य आदेश दिनांक 15.9.2009 द्वारा जीओएमएस संख्या 850 दिनांक 24.9.1991 में लागू सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जहां तक कि सर्वेक्षण संख्या 36 में एकड़ 90-00 की कुल सीमा तक रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा रखी गई भूमि थी। 37 चिंतित हैं और दिनांक 31.12.2004 के आक्षेपित नोटिस को भी रद्द कर दिया और तदनुसार रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। समान उत्तरदाताओं 1 और 2 से व्यथित होकर अर्थात् सरकार ने 2010 की रिट अपील संख्या 273 और 323 और उच्च की डिवीजन बेंच में अपील की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 8.6.2010 के सामान्य निर्णय द्वारा दोनों रिट अपीलों को खारिज कर दिया। उसी को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है। 2010 की रिट अपील 323 में प्रतिवादी संख्या 13 ने भी इस न्यायालय के समक्ष एक स्वतंत्र अपील को प्राथमिकता दी है और तीनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई की जाती है।

6. अपीलकर्ता राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री नागेश्वर राव ने तर्क दिया कि भूमि जागीरदारों के पास 'मुकुट

अनुदान' के रूप में थी और यह विरासत योग्य नहीं थी और जागीर प्रणाली 15.8.1948 को समाप्त कर दी गई थी और संपूर्ण जागीर भूमि कानून के संचालन से यह सरकार के अधीन हो गया और वर्ष 1950-52 के लिए एपी (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि विनियमन, 1358, फसली में अधिकारों के रिकॉर्ड के तहत तैयार किए गए भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि सर्वेक्षण संख्या 36 और 37 में शामिल थी। गोपनपल्ली गांव का स्वामित्व सरकार के पास था और इसे "चारागाह भूमि (कांचा चीन सरकारी गैर कृषि) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 1953-54 के लिए फैसल-पट्टी नामक भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, उक्त भूमि" सरकारी चरागाह भूमि " बनी रही। . उनका आगे कहना है कि अगस्त 1997 में पहली बार प्रतिवादी संख्या 1-12 ने 1997 की रिट याचिका संख्या 21719 दायर करके सर्वेक्षण संख्या 36 और 37 में 75 एकड़ जीटीएस पर अपने पूर्ववर्ती दर्ज नाम के आधार पर अधिकार प्राप्त करने का दावा किया था। 1954-55 का खसरा पिहानी

जबकि सर्वेक्षण संख्या 36 और 37 का कोई उप-विभाजन कभी नहीं किया गया था और भूमि कर्मचारी सहकारी समितियों को भूमि के एक समेकित भूखंड के रूप में आवंटित की गई थी जैसा कि सरकारी रिकॉर्ड में दिखाया गया है। अपीलकर्ताओं के अनुसार प्रतिवादियों के विक्रेता के नाम वर्ष 1954-55 में तत्कालीन पटवारी द्वारा कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश के बिना गुप्त रूप से

खसरा पहानी में दर्ज किए गए हैं और किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। केवल फर्जी प्रविष्टियों के आधार पर।

7. उनका आगे का तर्क यह है कि उच्च न्यायालय इस बात को समझने में विफल रहा कि सरकार को लंबे समय के अंतराल का हवाला देकर खसरा पिहानी में फर्जी प्रविष्टियों को सही करने के लिए कार्यवाही करने से नहीं रोका जा सकता है और रिट अपीलों को खारिज करना कानून में टिकाऊ नहीं है। अन्य अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर वेंकटरामनी ने भी उन्हीं कारणों से आक्षेपित आदेश की आलोचना की। उनकी दलीलों के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया था।

कलेक्टर और अन्य बनाम पी. मंगम्मा और अन्य (2003) 4 एससीसी 488 के फैसले में इस न्यायालय ने आंध्रप्रदेश आवंटित भूमि (स्थानांतरण निषेध) अधिनियम, 1977 के तहत अनियमित असाइनमेंट के खिलाफ स्वत: संज्ञान कार्रवाई से निपटते हुए कहा कि यह कठिन होगा। "उचित" शब्द की सटीक परिभाषा देने के लिए और एक उचित अवधि संबंधित मामले के तथ्यों और उस मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी जिसमें निर्णय लिया गया था, तीस साल की अवधि के बाद की गई स्वत: प्रेरणा की कार्रवाई को भेजा गया था। नये सिरे से विचार हेतु उच्च न्यायालय।

महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम रतनलाल (1993) 3 एससीसी 326 के फैसले में इस न्यायालय ने महाराष्ट्र कृषि भूमि (सीलिंग और होल्डिंग्स)

अधिनियम, 1961 की धारा 45 के तहत पुनरीक्षण शक्ति से निपटते हुए माना कि स्वत: प्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आक्षेपित आदेश की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति, तथापि जहां भौतिक तथ्यों का दमन, अर्थात् अघोषित कृषि भूमि का अस्तित्व, लंबे समय के अंतराल के बाद उच्च अधिकारियों के ज्ञान में आया था, सीमा तभी लागू होगी धोखाधड़ी या दमन की खोज की तारीख से।

उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम ब्रुंदबन शर्मा और अन्य (1995) अनुपूरक (3) एससीसी 249 के फैसले में इस न्यायालय ने उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1951 की धारा 38-बी के तहत संशोधन की शक्ति से निपटते हुए माना कि बोर्ड राजस्व ने पट्टा के कथित अनुदान की तारीख के 27 साल बाद पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया लेकिन इसकी प्रामाणिकता और शुद्धता संदिग्ध विशेषताओं से घिरी हुई थी और इसलिए, पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग कानूनी और वैध था।

8. हमने श्री यू.यू. ललित, श्री प्रवीण एच.पारेख, श्री रंजीत कुमार, श्री पी.वी. शेट्टी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित अन्य विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की मुख्य दलीलें यह हैं कि वर्ष 1954-55 के खसरा पहानी में उत्तरदाताओं के स्वामित्व में पूर्ववर्तियों के नाम का उल्लेख पाया गया है और उत्तरदाताओं द्वारा उनसे संबंधित भूमि की खरीद पंजीकृत के तहत की गई है। बिक्री विलेख विवाद में नहीं हैं और वे वर्ष 1954 से

लगातार नियमित रूप से भू-राजस्व का भुगतान कर रहे हैं और विषय संपत्ति के निरंतर कब्जे और आनंद के कारण उत्तरदाताओं को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हुए हैं और लंबे समय के अंतराल के बाद स्वत: पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया गया है। समय मनमाना है और जांच का सारांश उपाय और अभिलेखों में सुधार तब लागू नहीं किया जा सकता जब स्वामित्व का वास्तविक विवाद हो और अपीलकर्ताओं को सिविल मुकदमा दायर करके इसके समाधान निकालने की स्वतंत्रता दी गई है और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष टिकाऊ हैं। तथ्य और कानून. उनकी दलीलों के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा गया था।

गुजरात राज्य बनाम पाटिल राघव नाथ और अन्य (1969) 2 एससीसी 187 के फैसले में इस न्यायालय ने बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड, 1879 की धारा 65 और 211 का हवाला देते हुए कहा कि हालांकि धारा 211 के तहत कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है। अधिनियम की धारा 65 के तहत दिए गए आदेश को संशोधित करने के लिए, उक्त शक्ति का प्रयोग उचित समय में किया जाना चाहिए और उस मामले के तथ्यों पर जिसमें निर्णय हुआ, आदेश के एक वर्ष से अधिक समय बाद शक्ति का प्रयोग किया गया और वह था माना गया कि बहुत देर हो चुकी है।

मोहम्मद कवि मोहम्मद अमीन बनाम फातमाबाई इब्राहिम (1997) 6 एससीसी 71 के फैसले में इस न्यायालय ने बॉम्बे किरायेदारी और कृषि

भूमि अधिनियम, 1976 की धारा 84-सी से निपटते हुए माना कि हालांकि उक्त धारा शुरुआत के लिए किसी भी समय सीमा का निर्धारण नहीं करती है। आगे बढ़ने की ऐसी शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए और मामले के तथ्यों पर, नौ महीने की अवधि के बाद उक्त धारा के तहत शुरू की गई स्वत: संज्ञान जांच को उचित समय से परे माना गया।

संतोषकुमार शिवगोंडा पाटिल और अन्य बनाम बालासाहेब तुकाराम शेवाले और अन्य (2009) 9 एससीसी 352 के फैसले में इस न्यायालय ने महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 257 के तहत पुनरीक्षण की शक्ति से निपटते हुए इस प्रकार कहा:

"11. यह बिल्कुल तय प्रतीत होता है कि यदि कोई क़ानून पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है; बल्कि इसका प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून लंबे समय के अंतराल के बाद तय की गई चीज के अस्थिर होने की उम्मीद नहीं करता है। जहां विधायिका किसी भी अवधि के लिए प्रावधान नहीं करती है जिसके भीतर प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाना है, स्वतः प्रेरणा से या अन्यथा यह स्पष्ट है कि उचित समय के भीतर ऐसी शक्ति का प्रयोग अंतर्निहित है।

12. आमतौर पर, उचित अवधि जिसके भीतर पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, वह महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता की धारा 257 के तहत

तीन वर्ष होगी, बेशक, एक निश्चित आसानी में असाधारण परिस्थितियों के अधीन, लेकिन निश्चित रूप से एक चूक के बाद पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 257 के तहत उप-विभागीय अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण शक्ति का उपयोग करना 17 वर्ष की अवधि का उचित समय नहीं है, यह स्पष्ट रूप से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रक्रिया का दुरुपयोग है, यह मानते हुए कि तहसीलदार का आदेश पारित हो गया है 30-3-1976 त्रुटिपूर्ण है और कानूनी रूप से सही नहीं है।"

पंजाब राज्य और अन्य बनाम भटिंडा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (2007) 11 एससीसी 363 के फैसले में इस न्यायालय ने पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 21 के तहत पुनरीक्षण शक्ति से निपटते हुए इस प्रकार कहा:

"17. अधिनियम की धारा 21 को पढ़ने से पता चलता है कि यद्यपि इसके लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि स्वत: प्रेरणा शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है।

18. यह सामान्य बात है कि यदि कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है, तो वैधानिक प्राधिकारी को उचित अवधि के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। हालाँकि, उचित अवधि क्या होगी यह क़ानून की

प्रकृति, उसके तहत अधिकारों और देनदारियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा।

19. हमारी राय में, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग आम तौर पर उक्त अधिनियम के संदर्भ में उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तीन साल की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, इसकी अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए....."

इब्राहिम पटनम तालुक व्यवसायी कुली संघम बनाम के. सुरेश रेड्डी और अन्य (2003) 7 एससीसी 667 के फैसले में इस न्यायालय ने आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) की धारा 50-बी (4) के तहत पुनरीक्षण की स्वत: प्रेरणा शक्ति का उल्लंघन किया। किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 इस प्रकार आयोजित किया गया:

"9. ..... आवश्यक और पर्याप्त विवरणों के अभाव में धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की खोज की तारीख या अवधि के संबंध में दलील दी गई और इससे भी अधिक जब यह तर्क दिया गया कि स्वत: संज्ञान शक्ति धोखाधड़ी की खोज की तारीख से एक उचित अवधि के भीतर प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा आग्रह नहीं किया गया था, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच गैर-आधिकारिक द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी के सवाल की जांच नहीं करने में सही थी। उत्तरदाताओं। की धारा 50-बी की उपधारा (4) में "किसी भी समय" शब्दों का प्रयोग

अधिनियम केवल यह इंगित करता है कि सीमा की कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं है जिसके भीतर सलाह और प्रासंगिक रूप से किसी विशेष तिथि से गणना या शुरू करने के लिए स्वत: प्रेरणा शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। स्वत: संज्ञान की शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। धोखाधड़ी के मामलों में, इस शक्ति का प्रयोग धोखाधड़ी का पता चलने या खोजे जाने की तारीख से उचित समय के भीतर किया जा सकता है। ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय, कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जैसे कि काफी समय बीतने के कारण अचल संपत्ति पर तीसरे पक्ष के अधिकारों पर प्रभाव, बाद में वास्तविक हस्तांतरण द्वारा हाथों में बदलाव के प्रावधानों के तहत आदेशों को अंतिम रूप देना। अन्य अधिनियम (जैसे कि भूमि सीमा अधिनियम)। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 50-बी की उप-धारा (4) में परिसीमा की अवधि किस तारीख से शुरू होती है और किस अवधि के भीतर स्वत: शक्ति का प्रयोग किया जाना है, यह बताए बिना , "किसी भी समय" शब्दों का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि पार्टियों के अधिकारों की प्रकृति और क़ानून के संदर्भ में प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर धोखाधड़ी की खोज की तारीख से उचित अवधि के भीतर स्वत: संज्ञान शक्ति का प्रयोग किया जा सके। अधिनियम की धारा 50-बी की उपधारा (4) में "किसी भी समय" शब्दों के प्रयोग को अक्षरशः सख्ती से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसे प्रासंगिक और तर्कसंगत रूप से पढ़ा और समझा जाना चाहिए। यदि किसी को "किसी भी समय" शब्दों के

शब्दकोश अर्थ के आधार पर आगे बढ़ना है, तो अधिनियम की धारा 50-बी की उप-धारा (4) के तहत स्वत: संज्ञान शक्ति का प्रयोग दशकों के बाद भी किया जा सकता है और फिर यह इससे स्थिति सामान्य हो जाएगी, जिससे अनिश्चितता और जटिलताएं पैदा होंगी, जिससे पक्षों के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित होंगे, वह भी अचल संपत्तियों पर। पारित आदेशों के आलोक में पार्टियों के अधिकारों की अंतिमता और निश्चितता प्राप्त करने वाले आदेशों में पवित्रता होनी चाहिए। "किसी भी समय" स्वत: संज्ञान शक्ति का प्रयोग करने का अर्थ केवल यह है कि किसी विशेष तिथि से दिन, महीने या वर्ष जैसी कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं की जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि "किसी भी समय" दिशाहीन और मनमाना होना चाहिए। इस दृष्टिकोण में, "किसी भी समय" को सीमा की निर्धारित अवधि के अभाव में प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित समय के भीतर समझा जाना चाहिए।

9. 1948 में हैदराबाद राज्य के भारत में विलय के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) द्वारा जागीरें समाप्त कर दी गईं, जागीर विनियमन का उन्मूलन, 1358 फसली 'खसरा पहानी' राजस्व बोर्ड आंध्र प्रदेश द्वारा तैयार किया गया अधिकारों का मूल रिकॉर्ड है। वर्ष 1954-55 में. इसे एपी (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि विनियमन 1358 एफ में अधिकारों के रिकॉर्ड के विनियमन 4 के तहत राजपत्रित किया गया था। विनियमन संख्या 13 के अनुसार अधिकारों के उक्त रिकॉर्ड में कोई भी प्रविष्टि तब तक सत्य मानी

जाएगी जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए। 1358-एफ का उक्त विनियमन तब तक प्रचलन में था जब तक कि इसे एपी राइट्स इनलैंड एंड पट्टादार पास बुक्स एक्ट, 1971 द्वारा निरस्त नहीं कर दिया गया, जो 15.8.1978 को लागू हुआ। पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित "द लॉ लेक्सिकन" के दूसरे संस्करण (1997) में (पृष्ठ 1053 पर) 'खसरा' का वर्णन इस प्रकार किया गया है:

"खसरा एक कार्यकाल की घटनाओं को दर्ज करने वाला एक रजिस्टर है और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। खसरा स्वामित्व विलेख के उद्देश्य को पूरा करेगा, जब कोई अन्य शीर्षक विलेख न हो।"

10. माना जाता है कि गोपनपल्ली गांव के सर्वेक्षण संख्या 36 और 37 से संबंधित वर्ष 1954-55 के खसरा पहानी में उत्तरदाताओं के शीर्षक में पूर्ववर्तियों के नाम का उल्लेख मिलता है। उत्तरदाताओं द्वारा उनके तहत पंजीकृत विक्रय पत्रों से उक्त भूमि की खरीद भी गंभीर रूप से विवादित नहीं है। आगे तथ्य यह है कि वे वर्ष 1954 से लगातार नियमित रूप से भू-राजस्व का भुगतान कर रहे हैं। यहां अपीलकर्ताओं ने एपी (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि राजस्व अधिनियम, 1317 एफ (1907) की धारा 166 बी के तहत रद्द करने के लिए दिनांक 31.12.2004 को आक्षेपित नोटिस जारी किया। वर्ष 1953-54 के खसरा पिहानी में प्रविष्टियाँ, जाँच की तारीख 5.2.2005 निर्धारित करके और वह नोटिस यहाँ चुनौती का विषय है।

विनियम 166 बी इस प्रकार है:

"166-बी. संशोधन:-

(1) आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रेगुलेशन, 1358 एफ के प्रावधानों के अधीन, सरकार या कोई भी राजस्व अधिकारी जो कलेक्टर से कम रैंक का न हो, भूमि रिकॉर्ड का निपटान आयुक्त किसी मामले का रिकॉर्ड मांग सकता है। या किसी अधीनस्थ विभाग की कार्यवाही और स्वयं को संतुष्ट करने के लिए इसका निरीक्षण करता है कि पारित आदेश या निर्णय या की गई कार्यवाही नियमित, कानूनी और उचित है और उस संबंध में उपयुक्त आदेश दे सकता है;

बशर्ते कि रैयत के अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी भी आदेश या निर्णय को तब तक संशोधित या रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित पक्षों को बुलाया और सुना न जाए।

(2) कलेक्टर या सेटलमेंट कमिश्नर से निचले स्तर का प्रत्येक राजस्व अधिकारी किसी अधीनस्थ विभाग के मामले या कार्यवाही के रिकॉर्ड मांग सकता है और खुद को संतुष्ट कर सकता है कि पारित आदेश या निर्णय या की गई कार्यवाही नियमित, कानूनी और उचित है और यदि यदि उसकी राय में किसी भी आदेश या निर्णय या कार्यवाही को संशोधित या रद्द किया जाना चाहिए, तो वह मामले की फाइल रखेगा और अपनी राय के साथ कलेक्टर या सेटलमेंट कमिश्नर के पास जैसा भी मामला हो। इसके बाद

कलेक्टर या सेटलमेंट कमिश्नर उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

(3) मूल आदेश या निर्णय या मूल आदेश या निर्णय की एक प्रामाणिक प्रति जिसे संशोधित करने की मांग की गई है, संशोधन के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ दायर की जाएगी।

11. उपरोक्त विनियमन में स्वत: प्रेरणा शक्ति के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्वत: प्रेरणा शक्ति का प्रयोग 50 वर्षों की अवधि के बाद किया जा सकता है। सरकार ने वर्ष 1991 की शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास-स्थलों के लिए गोपनपल्ली गांव के सर्वेक्षण संख्या 36 और 37 में 477 एकड़ भूमि आरक्षित करने का आदेश पारित किया था। दूसरे शब्दों में, सरकार के पास दिनांक 24.9.1991 के सरकारी आदेश को पारित करते समय उक्त भूमि से संबंधित राजस्व प्रविष्टियों को सत्यापित करने का हर अवसर था, लेकिन पाई गई प्रविष्टियों पर कोई अपवाद नहीं लिया गया। इसके अलावा उत्तरदाताओं ने 1997 की रिट याचिका संख्या 21719 दायर की

दिनांक 24.9.1991 के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई और उस समय भी उक्त सर्वेक्षण संख्याओं में प्रविष्टियों के संबंध में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 से जमीन के खरीददारों ने 2001 के ओएस नंबर 12 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रंगा रेड्डी जिले की फाइल

पर एक सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें यह घोषणा करने की प्रार्थना की गई कि वे कुछ भूखंडों के वैध मालिक और धारक हैं। सर्वेक्षण संख्या 36 में भूमि, और प्रतियोगिता के बाद, मुकदमे की डिक्री की गई और उक्त डिक्री को अंतिम बनने की अनुमति दी गई। दिनांक 31.12.2004 के आक्षेपित नोटिस द्वारा ऊपर उल्लिखित विनियम 166 बी के तहत स्वत: संशोधन शक्ति का प्रयोग पांच दशकों के बाद करने की मांग की गई है और यदि इसे ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो इससे विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी जिससे अनिश्चितता और जटिलताएं पैदा होंगी जो पक्षो के अचल संपत्तियों पर गंभीर रूप से अधिकारों को प्रभावित करेंगी।

12. ऊपर जो कहा गया है उसके आलोक में हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण की पुष्टि करने में सही किया था कि लंबे समय के अंतराल के बाद स्वत: संज्ञान लिया गया पुनरीक्षण किया गया था। किसी भी सीमा अवधि के अभाव में भी यह मनमाना था और कानून के शासन की अवधारणा के विपरीत था।

13. इस प्रकार, हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती। परिणामस्वरूप उन्हें लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना बर्खास्त कर दिया जाता है।

न्यायाधिपति टी.एस. ठाकुर 1. मुझे अपने आदरणीय भाई न्यायाधिपति सी. नागप्पन द्वारा प्रस्तावित आदेश को पढ़ने का सौभाग्य मिला है। हालांकि मैं

उनके आधिपत्य द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूं कि एपी (तेलंगाना क्षेत्र) की धारा 166 बी के तहत पुनरीक्षण शक्तियां संयुक्त कलेक्टर में निहित हैं। कथित फर्जी प्रविष्टियों के निर्माण के 50 साल बाद भूमि राजस्व अधिनियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को 31 दिसंबर, 2004 को जारी किए गए नोटिस को रद्द करना उचित ठहराया था, मैं अपनी खुद की कुछ पंक्तियां जोड़ना चाहूंगा।

2. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं और रिट अपीलों को दाखिल करने को जन्म देने वाले तथ्य, जिनसे वर्तमान अपीलें उत्पन्न होती हैं, मेरे सम्मानित भाई द्वारा उनके द्वारा प्रस्तावित आदेश में विस्तार से बताए गए हैं। इसलिए, तथ्यात्मक मैट्रिक्स का फिर से वर्णन करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यह कहना पर्याप्त होगा कि इन कार्यवाही में विवाद सर्वेक्षण संख्या 36 में स्थित 44 एकड़ भूमि और सर्वेक्षण संख्या 37 में 46 एकड़ भूमि तक सीमित है। आंध्र प्रदेश राज्य के रंगा रेड्डी जिले के गोपनपल्ली गाँव का। उत्तरदाताओं (उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं) का मामला यह था कि भूमि की उक्त सीमा संबंधित जागीरदार द्वारा पट्टे पर वास्तविक खेती करने वाले व्यक्तियों को दी गई थी। उत्तरदाताओं के अनुसार, पट्टा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1954-55 से खातेदारों के नाम खसरा फानों में दर्शाए गए हैं

3. जी.ओ.एम. 850 रिविज़न (एएसएन.111) विभाग दिनांक 24 सितंबर, 1991 के संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आवास स्थल प्रदान करने के लिए गोपनपल्ली गांव के सर्वेक्षण संख्या 36 और 37 में 477 एकड़ भूमि आवंटित की है। इसके बाद संयुक्त कलेक्टर, रंगा रेड्डी जिले से 31 दिसंबर, 2004 को एक नोटिस आया, जिसके तहत रिट-याचिकाकर्ताओं (यहाँ प्रतिवादियों) को 5 फरवरी, 2-005 को यह बताने के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया कि खसरा फानी प्रविष्टियों के संबंध में क्यों उपरोक्त गांव में स्थित सर्वे नंबर 36 की 460.07 एकड़ और सर्वे नंबर 37 की 424.17 एकड़ जमीन को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी आदेश और कारण बताओ नोटिस से व्यथित होकर रिट याचिकाएँ संख्या 21719 वर्ष 1997 और 1731 वर्ष 2005 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गईं जो कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांक 15 सितंबर, 2009 द्वारा निपटारा किया गया। उच्च न्यायालय का विचार था कि वर्ष 1954-55 के लिए खसरा पहानी में प्रविष्टियाँ पूर्ववर्तियों के नामों को प्रतिबिंबित करती हैं। -रिट याचिकाकर्ताओं का हक हालांकि सरकार के मुताबिक उक्त प्रविष्टियां गांव के तत्कालीन पटवारी द्वारा फर्जी तरीके से की गई थीं। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि चूँकि सरकार द्वारा 24 सितंबर, 1991 को जी.ओ.एम. 850 रिविज़न (एएसएन.111) विभाग जारी करने से पहले लगभग 40 वर्षों तक रिट याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व और कब्जे को दर्शाने वाली प्रविष्टियाँ बिना किसी चुनौती के जारी रहीं, इसलिए सरकार के लिए कोई भी ऐसा करना

उचित नहीं था। इसकी उपेक्षा करते हुए आवंटन किया गया। उच्च न्यायालय ने यह भी विचार किया कि प्रविष्टियाँ पहली बार किए जाने के लगभग 50 साल बाद कथित धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों का प्रस्तावित सुधार भी कानूनी रूप से अस्वीकार्य था, तब भी जब ऐसा करने के लिए पुनरीक्षण शक्ति लागू की गई थी, जिसमें कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि रिट-याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्ती-इन-टाइटल ने उनके पक्ष में बिक्री विलेख पंजीकृत किए थे और राज्य सरकार या उसके अधिकारियों ने इस बात से इनकार नहीं किया था कि रिट-याचिकाकर्ताओं या उनके पूर्ववर्ती-इन-टाइटल के पास संपत्ति का कब्जा बना हुआ था। विषय भूमि उच्च न्यायालय ने माना कि पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग, भले ही कोई सीमा अवधि निर्धारित न हो, उचित अवधि के भीतर होनी चाहिए।

4. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने 2010 की रिट अपील संख्या 273-323 को प्राथमिकता दी, जिसे 8 जून, 2010 के अपने आदेश के अनुसार उस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने भी खारिज कर दिया था। डिवीजन बेंच ने इस पर भरोसा करते हुए संतोषकुमार शिवगोंडा पाटिल और अन्य बनाम बालासाहेब तुकाराम शेवाले (2009) 9 एससीसी 352 और विशेष निदेशक और अन्य बनाम मोहम्मद गुलाम घोष और अन्य (2004) 3 एससीसी 440 में इस न्यायालय के फैसलों

ने माना कि राजस्व प्रविष्टियों में प्रस्तावित सुधार 50 साल बाद किया गया था। जो कुछ भी किया गया वह कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं था। वर्तमान अपीलें उस दृष्टिकोण की सत्यता पर सवाल उठाती हैं।

5. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रिट-याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज तत्कालीन पट्टादारों से सर्वेक्षण संख्या 36 और 37 में 90 एकड़ जमीन खरीदी है। इसलिए, वर्तमान विवाद केवल भूमि की सीमा तक ही सीमित है। ऐसा होने पर, यदि एपी (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 166 बी के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाले नोटिस पर किसी अन्य प्रभावित पक्ष द्वारा हमला नहीं किया गया है, तो हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ हस्तक्षेप करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यह कहते हुए कि एकमात्र प्रश्न जो उच्च न्यायालय ने संबोधित किया है और जिस पर उसके द्वारा आक्षेपित आदेशों में विस्तृत रूप से निपटा गया है, वह यह है कि क्या उपरोक्त अधिनियम की धारा 166 बी के तहत सक्षम प्राधिकारी में निहित पुनरीक्षण शक्तियों को कथित धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियाँ किए जाने के 50 साल बाद लागू किया जा सकता है। अपीलकर्ता की ओर से दलील मुख्य रूप से यह थी कि चूंकि ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के तहत पुनरीक्षण शक्तियों को लागू करने के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है, इसलिए उसी हस्तक्षेपकारी देरी के अभ्यास में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उस दृष्टिकोण में न तो कोई त्रुटि है और न ही कोई विकृति। इस न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला

से कानूनी स्थिति काफी हद तक ठीक हो गई है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि भले ही किसी पुनरीक्षण या अन्यथा शक्ति के प्रयोग के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित न हो, ऐसी शक्ति का प्रयोग उचित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। . ऐसा उन मामलों में भी है जहां धोखाधड़ी के आरोपों के लिए किसी सुधारात्मक शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो गया है। हम संक्षेप में कुछ निर्णयों का उल्लेख केवल इस बात को सामने लाने के लिए कर सकते हैं कि जहां तक शक्ति के प्रयोग का संबंध है, सीमा की निर्धारित अवधि के अभाव से बहुत कम या कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसे केवल तभी अनुमति दी जानी चाहिए जब शक्ति हो। उचित अवधि के भीतर लागू किया गया।

6. एस.बी. गुरबख्श सिंह बनाम भारत संघ 1976 (2) एससीसी 181 में इस न्यायालय के पहले निर्णयों में से एक में, इस न्यायालय ने माना था कि पुनरीक्षण की स्वत: प्रेरणा शक्ति का प्रयोग भी उचित समय के भीतर होना चाहिए और किसी भी अनुचित देरी के लिए अभ्यास में वैधता प्रभावित हो सकती है। लेकिन उचित समय क्या होगा यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

7. इसी प्रभाव के लिए इब्राहिमपटनम में इस न्यायालय का निर्णय 'तालुक व्यवसायी कुली संघम वी. के. सुरेश रेड्डी और अन्य (2003) 7 एससीसी 667 है जहां इस न्यायालय ने माना कि धोखाधड़ी के मामलों में भी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। उचित अवधि और यह निर्णय लेते

समय कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या केवल देरी के आधार पर जल्द राहत देने से इनकार कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा:

"धोखाधड़ी के मामलों में, इस शक्ति का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने या खोज की तारीख से उचित समय के भीतर किया जा सकता है। ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय, कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जैसे कि तीसरे पक्ष के अधिकारों पर प्रभाव काफी समय बीतने के कारण अचल संपत्ति, बाद में वास्तविक हस्तांतरण द्वारा हाथों में बदलाव, अन्य अधिनियमों (जैसे भूमि सीमा अधिनियम) के प्रावधानों के तहत आदेशों को अंतिम रूप देना।"

8. इसी आशय का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा सुलोचना चंद्रकांत गलांडे बनाम पुणे नगर परिवहन और अन्य (2010) 8 एससीसी 467 में लिया गया है, जहां इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को दोहराया और माना कि आदेशों और कार्यवाही को संशोधित करने की शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है और अनवरत। इस न्यायालय ने कहा:

"विधानमंडल ने अपने विवेक से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की और न ही 1976 के अधिनियम की धारा 34 में "किसी भी समय" शब्द डाले। इसका मतलब यह नहीं है कि विधायिका का इरादा इसके तहत पारित आदेशों को छोड़ने का था। अधिनियम अनिश्चित काल के लिए बदलाव के लिए खुला है क्योंकि इससे धारकों/आवंटियों का स्वामित्व स्थायी रूप से अनिश्चित और निरंतर

अनिश्चितता की स्थिति में पहुंच जाएगा। मामले में, यह माना जाता है कि विधायिका ने एक शाश्वत प्रदान किया है और समय के बिंदु पर अनंत शक्ति, शीर्षक पर

घोषित अधिशेष भूमि, राज्य-आबंटिती के हाथों में, हमेशा के लिए लगभग असुरक्षित बनी रहेगी। न्यायालय को वैधानिक प्रावधान को इस तरह समझना होगा जो प्रावधानों को व्यावहारिक बनाए, जिससे कानून के अधिनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके।"

9. हिमाचल प्रदेश राज्य में और अन्य बनाम राजकुमार बृजेंद्र सिंह और अन्य (2004) 10 एससीसी इस न्यायालय ने माना कि किसी विशेष परिस्थिति के अभाव में स्वत: संज्ञान से पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में 15 साल की देरी स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि देरी अनावश्यक रूप से लंबी और अस्पष्ट थी। इस न्यायालय ने कहा:

"अब हमारे पास दूसरा प्रश्न बचा है जो प्रतिवादियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था, वह है धारा 20 की उप-धारा (3) के तहत शक्ति के विलंबित प्रयोग। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्तीय आयुक्त ने कलेक्टर के आदेश के 15 साल बाद शक्ति का प्रयोग किया। यह सच है कि उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है लेकिन इस अभिव्यक्ति का मतलब यह नहीं है कि कोई समय-सीमा नहीं होगी या यह अनंत में है। तात्पर्य यह है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। सीमा की कोई निश्चित

अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, लेकिन शक्ति के प्रयोग में अनुचित देरी उन चीजों को पूर्ववत कर देगी जो अंतिम रूप ले चुकी हैं। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उचित समय क्या है जिसके भीतर स्वत: कार्रवाई की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इस मामले में, चूँकि अपील वापस ले ली गई थी, लेकिन वित्तीय आयुक्त ने अपनी स्वत: प्रेरणा शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले को उठाया था, राज्य के लिए यह प्रस्तुत करना खुला हो सकता है कि तथ्य और परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि यह होगा उचित समय के भीतर लेकिन जैसा कि हमने पहले ही नोट किया है कि कलेक्टर के जिस आदेश में हस्तक्षेप किया गया है वह जनवरी 1976 में पारित किया गया था और राज्य द्वारा की गई अपील भी मार्च 1976 में किसी समय वापस ले ली गई थी। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ऐसे अन्य विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को इंगित करने में सक्षम नहीं थे जिनके कारण यह कहा जा सकता था कि आदेश में हस्तक्षेप के 15 वर्षों के बाद स्वत: संज्ञान शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया गया था। हमारे विचार में यह स्थिति होने के कारण, वित्तीय आयुक्त का आदेश 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पारित होने के कारण रद्द हो गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया गया है। इसलिए, यह मानते हुए कि वित्तीय आयुक्त के पास उपयुक्त मामले में स्वत: संज्ञान लेकर आगे बढ़ने की शक्ति होगी, भले ही निचले अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष की गई अपील राज्य द्वारा वापस ले ली गई हो। इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण टिकाऊ नहीं है। लेकिन वित्तीय आयुक्त का आदेश

समय की अनुचित चूक के बाद शक्ति के प्रयोग के दोष से ग्रस्त है और उनकी ओर से इस तरह की विलंबित कार्रवाई धारा 20 की उपधारा (3) के तहत शक्ति के प्रयोग में उनके द्वारा पारित आदेश को रद्द कर देती है।

10. हम मेसर्स डेहरी रोहतास लाइट रेलवे कंपनी लिमिटेड वी. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भोजपुर और अन्य (1992) 2 एससीसी 598 में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं जहां न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नानुसार समझाया:

"वह नियम जो कहता है कि न्यायालय विलंबित और पुराने दावे की जांच नहीं कर सकता है, कानून का नियम नहीं है बल्कि विवेक के उचित और उचित प्रयोग पर आधारित अभ्यास का नियम है। प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। यह सब इस पर निर्भर करेगा मौलिक अधिकार का उल्लंघन और दावा किए गए उपाय क्या हैं और देरी कैसे हुई। जिस सिद्धांत पर देरी या देरी के आधार पर पार्टी को राहत देने से इनकार किया जाता है, वह यह है कि जो अधिकार देरी के कारण दूसरों को प्राप्त हुए हैं याचिका दायर करने में तब तक खलल डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण न हो। ऐसे मामलों में देरी का निर्धारण करने के लिए वास्तविक परीक्षण यह है कि याचिकाकर्ता को समानांतर अधिकार बनाने से पहले रिट कोर्ट में आना चाहिए और इसकी समाप्ति समय किसी भी कमी या लापरवाही के लिए

जिम्मेदार नहीं है। परीक्षण समय के भौतिक संचालन से संबंधित नहीं है। जहां आचरण को उचित ठहराने वाली परिस्थितियां मौजूद हैं, वहां जो अवैधता प्रकट होती है उसे दर्द के एकमात्र आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता है। तिलोकचंद मामले में जिस निर्णय पर भरोसा किया गया वह वर्तमान मामले के तथ्यों पर भिन्न है। यदि रेलवे उपक्रम के शुद्ध मुनाफे पर आधारित लेवी अधिकार से परे थी और बाद के वर्षों से संबंधित मामले में उच्च न्यायालय की घोषणा के बाद लंबित कार्यवाही में देर से ही सही, इसकी अवैध प्रकृति पर सवाल उठाया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ता के दावे को देरी के एकमात्र आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को समय रहते खारिज करना और मांगी गई राहत देने से इनकार करना गलत था। हालाँकि हम इस बात से सहमत हैं कि मुकदमा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है"

11. संक्षेप में, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के विलंबित प्रयोग पर आपत्ति जताई जाती है क्योंकि यदि कार्य या लेनदेन हमेशा चुनौती के लिए खुले रहेंगे, तो इसका मतलब मानवीय मामलों में टालने योग्य और अंतहीन अनिश्चितता होगी, जो कानून की नीति नहीं है। क्योंकि, जब ऐसी शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं होती है, तब भी हस्तक्षेप करने वाली देरी, तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण का कारण बन सकती है, जिसे विवेकाधीन शक्ति के देर से अभ्यास द्वारा कुचला नहीं जा सकता है, खासकर

जब इसके लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है देरी दिख रही है. ऐसा कहा जाता है कि कानून का शासन जीवन के नियम के साथ मिलकर चलना चाहिए। यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां संशोधित किए जाने वाले आदेश धोखाधड़ी वाले हैं, शक्ति का प्रयोग धोखाधड़ी की खोज की उचित अवधि के भीतर होना चाहिए। किसी कार्य या लेन-देन को कपटपूर्ण बताने मात्र से उसके सुधार के लिए लगने वाला समय अनंत तक नहीं बढ़ जाएगा; अन्यथा पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग स्वयं उस क़ानून के साथ धोखाधड़ी के समान होगा जो ऐसी शक्ति किसी प्राधिकारी को प्रदान करता है।

12. मौजूदा मामले में, जबकि सुधार की मांग की गई प्रविष्टि को धोखाधड़ी के रूप में वर्णित किया गया है, उच्च न्यायालय के समक्ष लगाए गए नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि राज्य द्वारा कथित धोखाधड़ी की खोज कब की गई थी। उस संबंध में एक विशिष्ट बयान आवश्यक था क्योंकि यह एक न्यायिक तथ्य था, जिसे उत्तरदाताओं को जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। अपीलकर्ता-राज्य का यह प्रदर्शित करने का प्रयास कि कथित धोखाधड़ी की खोज की उचित अवधि के भीतर नोटिस जारी किया गया था, इसलिए व्यर्थ है। किसी भी दर पर, जब सरकार ने वर्ष 1991 में आवास स्थलों के लिए संबंधित भूमि को सरकारी कर्मचारियों को देने की अनुमति दी, तो यह माना जाना चाहिए कि उसे आधिकारिक व्यवसाय के सामान्य क्रम में भूमि के पार्सल से संबंधित रिकॉर्ड और राजस्व प्रविष्टियों के बारे में पता था। हालाँकि, नोटिस 31

दिसंबर, 2004 को जारी किया गया था, इसमें लगभग 13 साल की देरी हुई थी। इस देरी के लिए भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, यह मानते हुए कि इसे केवल वर्ष 1991 से गिना जाना चाहिए। किसी भी कोण से देखा जाए तो आधी सदी पहले की गई प्रविष्टियों को उलटने की मांग करने वाला नोटिस स्पष्ट रूप से उचित समय से परे था और इसे सही ढंग से रद्द कर दिया गया था।

13. यह कहने के बाद कि हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम कथित फर्जी प्रविष्टि की सत्यता पर नहीं गए हैं और न ही हमने कोई राय व्यक्त की है कि क्या 21 दिसंबर, 2004 के नोटिस को रद्द करने से राज्य को ऐसे अन्य कदम उठाने से रोका जा सकेगा। जैसा कि कानून के किसी भी प्रावधान के तहत अनुमत हो सकता है। उच्च न्यायालय ने वास्तव में यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार भूमि जांच के लिए कानून के अनुसार कोई अन्य कदम या कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी। वह स्वतंत्रता पर्याप्त होनी चाहिए क्योंकि हमने इस मामले की केवल संकीर्ण कोण से जांच की है कि क्या ए.पी. (तेलंगाना क्षेत्र) भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 166-बी के तहत सक्षम प्राधिकारी में निहित अनंतिम शक्तियों के प्रयोग से 1954-55 की खसरा फानी प्रविष्टि को इस विलंबित चरण में ठीक किया जा सकता है। उस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिए जाने के कारण ये अपीलें विफल

होनी चाहिए और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ कर खारिज कर दी जाती हैं।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।